Statement

Amount required for development of infrastructure—as presented by each State before the High Level Commission

(Rs. in crores)

Sector	Assam	Arunachal Pradesh	Tripura	Manipur	Mizoram	Meghalaya	Nagaland
Power	4122.90	847.00$	264.60	380.00$	1366.50	719.66	133.88
Roads	24735.00	1118.00	409.92	539.00	851.19	57.00	645.30
Railways	—	36.00	—	—	—	—	—
Irrigation	8091.62	Schemes under	350.00	744.41	52.26	77.54	60.00$$
Flood Control (Short-term measures only)	1194.00	Central Sector	600.00	60.00	—	—	—
Inland Water Transport	325.00	—	—	—	—	—	—

* Excluding large hydel projects kept under Central sector.
$ Including rural electrification.
kept under Central sector.
Major and medium irrigation, including Loktak Development.
*$ Irrigation and Land Development.

मध्य प्रदेश के गांवोंमें विद्युतीकरण

2024. **श्री अजीत जोगी:**
श्री मूलचन्द मीणा:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, मध्य प्रदेश के कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) कितने गांवों का विद्युतीकरण अभी किया जाना है तथा उनका जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन गांवों में विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में विद्युतीकृत किए गए गांवों की संख्या निम्नवत् है:—

वर्ष	विद्युतीकृत किए गए गांवो की संख्या
1993-94	751
1994-95	1019
1995-96	503

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश में जनवरी, 1997 के अंत तक 4,222 गांव विद्युतीकृत किए जाने के लिए शेष थे। ऐसे गांवों का जिलेवार ब्यौरा (संलग्न विवरण में दिया गया है।**(नीचे देखिए)**

(ग) ग्राम विद्युतीकरण एक सतत प्रक्रिया है और मध्य प्रदेश में शेष गांवों का विद्युतिकरण नौवीं तथा अनुवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं में किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, राज्य में विद्युत आपूर्ति की स्थिति, पारेषण एवं वितरण प्रणाली के कुल नेटवर्क तथा अन्य तत्संबंधी निवेशों पर निर्भर करेगा।

विवरण

मध्य प्रदेश के गांवों में विद्युतीकरण का जिला वार ब्यौरा

क्र० सं०	जिला	गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1.	भोपाल	2
2.	रायसेन	111
3.	विदिशा	107
4.	सिहोर	8
5.	होशंगाबाद	128
6.	राजगढ़	15

क्र. सं.	जिला	गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या
7.	बैतुल	20
8.	ग्वालियर	9
9.	दतिया	6
10.	मुरैना	71
11.	भिण्ड	11
12.	शिवपुरी	43
13.	गुना	100
14.	इंदौर	4
15.	धार	10
16.	झाबुआ	29
17.	खण्डवा	5
18.	खरगौन	138
19.	उज्जैन	0
20.	रतलाम	0
21.	मंदसौर	5
22.	शाजापुर	3
23.	देवास	7
24.	जबलपुर	125
25.	माण्डला	159
26.	नरसिंहपुर	9
27.	छिंदवाड़ा	14
28.	सिवोनी	69
29.	बालाघाट	108
30.	सागर	121
31.	दमोह	123
32.	रीवा	263
33.	सतना	164
34.	छतरपुर	19
35.	पन्ना	32
36.	टीकमगढ़	13
37.	सिद्दी	28
38.	शहडोल	173
39.	रायपुर	247
40.	दुर्ग	71
41.	राजनंदगांव	187
42.	बस्तर	726
43.	बिलासपुर	223
44.	सरगुजा	302
45.	रायगढ़	214
	जोड़ :	4222

Opposition to Privatisation of Power Projects

2025. SHRI S. M. KRISHNA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem capactioned "Power Engineers oppose privatisation" which appeared in the 'The Hindustan Times' dated the 23rd February, 1997, if so, Government's reaction thereto;

(b) the details of proposals for power projects in private sector received and those approved, State-wise during last three months, month-wise;

(c) whether it is a fact that World Bank loan of Rs. 5000 crores has been taken for privatisation of power sector; and

(d) if so, the terms and conditions of the loan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) No news-item captioned "Power Engineers opposed privatisation" appeared in the Hindustan Times dated 23rd February, 1997.

(b) Details of the schemes for setting up power projects in the private sector, for which the detailed project reports have been received in the Central Electricity Authority (CEA) during the last three months for examination for accrod of techno-economic clearance, are given in the statement (*See* below). following private sector power projects have been techno-economically cleared by CEA during December 1996 to February 1997;